

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 21, गुरुवार, शाके 1946- दिसम्बर 12, 2024 Agrahayana 21, Thursday, Saka 1946- December 12, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 18, 2024

संख्या प. 2(62)वन/2024 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है:-

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है:

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 26 की उप-धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11(1) 12,14,17,18,19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किए जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु-पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बीजो जाँय,
विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
1	अम्बासा- ए	झाडोल	उदयपुर	उत्तर - अम्बासा वनखण्ड दक्षिण - राजकीय भूमि पूर्व - राजकीय भूमि पश्चिम - गुजरात सीमा	ग्राम- अम्बासा	
					खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
					1983/1	21.60 है.
					1984/1	31.30 है.
					योग	52.90 है.

देवेन्द्र कुमार तिवाड़ी,
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर।

द्वितीय अनुसूची
पेड़ों की सूची

संख्या	बोटोनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1	Acacia catechu	Khair
2	Adina cordifolia	Haldu
3	Aegle marmelos	Bili
4	Alangium salvifolium	Ankol
5	Anogeissus latifolia	Dhavda
6	Azadirachta indica	Neem
7	Bombax ceiba	Semal
8	Boswellia serrata	Salar
9	Butea monosperma	Khakhro
10	Cassia fistula	Karmela
11	Cordia mixa	Gunda, Lisoda
12	Dalbergia latifolia	Sisam
13	Diospyros melanoxylon	Timru
14	Ficus racemosa	Umara
15	Ficus religiosa	Piplo
16	Holoptelia integrifolia	Kanji
17	Lannea coromandelica	Godla
18	Madhuca indica	Mahudo

19	Miliusa tomentosa	Umb
20	Moringa oleifera	Sahjana
21	Pongamia pinnata	Karanj
22	Terminalia bellarica	Baheda

देवेन्द्र कुमार तिवाड़ी,
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर।

परिशिष्ट 'क'

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,
वन्यजीव उदयपुर द्वारा प्रमाण-पत्र

वनखण्ड अम्बासा-ए

रैंज: पानरवा (वन्यजीव)

वन मण्डल: उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर

- संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः बिलानाम काबिल काशत जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या-6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है। जिला कलक्टर, उदयपुर के संशोधित आदेश क्रमांक प.39/1(5)राज/हस्ता./2005/ 5399-5405 दिनांक 27.12.2006 आदेश से मौजा अम्बासा तहसील झाडोल की आराजी नम्बर-1 रकबा 75.90 हेक्टर में से 21.60 हेक्टर तथा पत्रांक प.39/1(4)राज./हस्ता/ 2005/3332-38 दिनांक 02.06.2007 संशोधित आदेश से मौजा अम्बासा तहसील झाडोल की आराजी नम्बर-1 रकबा 54.30 हेक्टेयर में से 31.30 हेक्टर कुल 52.90 हेक्टर इस कार्यालय को आवंटित की गई है।
- उक्त प्रस्ताव में कुल वन भूमि 52.90 हेक्टेयर में से 31.30 हेक्टेयर भूमि "मामेर लघु सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्राप्त हुई। जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 15.05.2013 एवं अन्तिम स्वीकृति दिनांक 25.01.2016 को जारी हो चुकी है। शेष 21.60 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत "पानरवा से छाली बोकड़ा" एवं "सोम से सरवण" की सड़क परियोजना में क्रमशः 10.80 हेक्टेयर एवं 10.80 हेक्टेयर भूमि इस कार्यालय को प्राप्त हुई, अभयारण्य के भीतर पक्की सड़क निर्माण नहीं होने के कारण से उक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत दोनों प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। परन्तु भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद हो जाने के कारण से अम्बासा-ए वनखण्ड में उक्त भूमि को शामिल किया गया है।
- वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों के वन भूमि दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं कराया गया है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
- भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.3 से 0.6 है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों की सूची संलग्न द्वितीय अनुसूची के अनुसार है।
- वन भूमि के चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या-5 में कर दिया गया है।

6. वनखण्ड का वांछित मानचित्र (नक्शा) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी.टी.शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र की विज्ञप्ति के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्र को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिससे की इस भूमि पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

देवेन्द्र कुमार तिवाड़ी,
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।